



करेंट अफेयर्स

मध्य प्रदेश

दिसंबर

(संग्रह)

2024

अनुक्रम

मध्य प्रदेश	3
➤ भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल	3
➤ मध्य प्रदेश का 9वाँ टाइगर रिजर्व	4
➤ मध्य प्रदेश में प्रधान डाकघर का आधुनिकीकरण	6
➤ विश्व AIDS दिवस 2024 पर इंदौर में कार्यक्रम	6
➤ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा	8
➤ मध्य प्रदेश में नई योजनाएँ शुरू	10
➤ बैगा आदिवासी कलाकार जोधईया बाई का निधन	11
➤ मध्य प्रदेश ने चीता के लिये नया आवास बनाने की योजना	12
➤ भारत का पहला जीरो-वेस्ट हवाई अड्डा	13
➤ MP हाईकोर्ट ने मंदसौर में बूचड़खाने को NOC दी	14
➤ वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	14
➤ प्रधानमंत्री ने केन-बेतवा परियोजना की आधारशिला रखी	16
➤ मध्य प्रदेश में बाघों को स्थानांतरित किया जाएगा	16
➤ मध्य प्रदेश विषाक्त अपशिष्ट का निपटान करेगा	18
➤ रक्षा मंत्री ने महुँ स्थित आर्मी वॉर कॉलेज का दौरा किया	18

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

मध्य प्रदेश

भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल

चर्चा में क्यों ?

भोपाल गैस त्रासदी के चार दशक बाद भी, सरकारी अधिकारी, अनेक अदालती आदेशों और चेतावनियों के बावजूद, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) के परिसर में **मौजूद सैकड़ों टन जहरीले अपशिष्ट** का सुरक्षित निपटान करने में **विफल** रहे हैं।

मुख्य बिंदु

- ऐतिहासिक संदर्भ और निपटान चुनौतियाँ:
 - ◆ भोपाल गैस त्रासदी इतिहास की सबसे भयंकर औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक थी, जो 2-3 दिसंबर 1984 की रात को मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) के कीटनाशक संयंत्र में घटित हुई थी।
 - इससे लोगों और जानवरों को अत्यधिक जहरीली गैस **मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC)** के संपर्क में लाया गया, जिससे तत्काल और दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और मौतें हुईं।
 - ◆ वर्ष 1969 और 1984 के बीच **कीटनाशक उत्पादन** के दौरान उत्पन्न विषाक्त अपशिष्ट को साइट पर ही फेंक दिया गया, जिससे खतरनाक प्रथाओं और नियामक लापरवाही के कारण संदूषण और भी खराब हो गया।
 - ◆ वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपशिष्ट एकत्र किया, जिसका एक भाग जला दिया गया तथा 337 मीट्रिक टन अपशिष्ट को एक शेड में संग्रहित किया गया।
 - 2015 में, **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** ने परीक्षण के आधार पर 10 मीट्रिक टन को जला दिया तथा इसके बाद इसके निपटान की सिफारिश की, जो नहीं हुआ।
- सरकारी वित्तपोषण और विषाक्त अपशिष्ट निपटान:
 - ◆ केंद्र सरकार ने 2005 से यूनियन कार्बाइड परिसर में संग्रहीत 337 मीट्रिक टन विषाक्त अपशिष्ट के निपटान के लिये मध्य प्रदेश सरकार को 126 करोड़ रुपए जारी किये।
 - ◆ **2010 के एक अध्ययन से पता चला कि** इस स्थल पर 11 लाख टन दूषित मृदा, एक टन पारा और लगभग 150 टन भूमिगत अपशिष्ट मौजूद है तथा इस अपशिष्ट के निपटान की अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है।
 - रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2005 में अपशिष्ट का संग्रहण अधूरा था तथा सुधार के लिये **दफनाए गए विषाक्त अपशिष्ट की खुदाई की अनुशंसा की गई**।
 - ◆ प्रशासनिक बाधाओं के कारण 337 मीट्रिक टन अपशिष्ट का निपटान अभी तक शुरू नहीं हो पाया है।
- भूजल प्रदूषण:
 - ◆ अध्ययनों से पता चला है कि फैक्ट्री के निकट के रिहायशी इलाकों में **भूजल भारी धातुओं और जहरीले पदार्थों से दूषित है**, जिससे **कैंसर** और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ बरसात के मौसम में और अधिक प्रदूषण की चेतावनी देते हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- सरकार ने हैंडपंप और ट्यूबवेल को सील कर दिया है और फैक्ट्री के आस-पास के 42 इलाकों में सुरक्षित पेयजल का वितरण बढ़ा दिया है। हालाँकि, निवासी गैर-पीने के उद्देश्यों के लिये दूषित पानी का उपयोग करना जारी रखते हैं।
- ◆ इन उपायों के बावजूद, **भूजल प्रदूषण** बढ़ता जा रहा है, जिससे गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद भी नए पीड़ित सामने आ रहे हैं।
 - स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों में विषाक्त पदार्थों के लंबे समय तक संपर्क के कारण होने वाली गंभीर बीमारियाँ शामिल हैं।
- **न्यायिक और नियामक निरीक्षण:**
 - ◆ **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)** ने सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की तथा जल निकायों को प्रदूषित करने में रिसाव की भूमिका पर जोर दिया।
 - मार्च 2022 में छह महीने के भीतर अपशिष्ट निपटान का आदेश दिया गया था, लेकिन निर्देश अभी तक लागू नहीं हुआ है।
 - ◆ भूजल प्रदूषण की शिकायतों के बाद, **सर्वोच्च न्यायालय** ने राज्य को सुरक्षित जल तक पहुँच बढ़ाने और प्रदूषण की समस्या से निपटने का निर्देश दिया।

IMPACT OF GAS EXPOSURE		Key Demands
<p>▶ Younger population born after gas leak equally vulnerable</p> <p>▶ Those between 31 and 60 (which includes those born after the gas leak of 1984) account for 80% of the suffering</p> <p>59% Gas affected women suffered illnesses</p>	<p>Those under 40 years of age and exposed to gas leak, were diagnosed with twice as many illness as the non-gas leak exposed</p> <p>● Illness includes cardiac, cancer, respiratory, kidney, TB, typhoid and among others</p> <p>● Twice as many 'gas affected' are dying of cancers, respiratory illnesses -- compared with normal population</p> <p>● Kidney failure rate is 3 times, compared with non-gas affected</p>	<p>▶ To set up a system of registration of deaths of people with direct or indirect exposure</p> <p>▶ Over 5,000 gas victims are cancer patients. Review of the work of the Population Based Cancer Registry in Bhopal that claims that there is no association between gas exposure and cancer</p> <p>▶ Review the system of health-care in place for gas victims</p> <p>▶ Urgently review drug utilization in the care of gas exposed persons to avoid kidney damage</p>

मध्य प्रदेश का 9वाँ टाइगर रिज़र्व

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने शिवपुरी ज़िले में **माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिज़र्व** के रूप में मान्यता देने की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, माधव मध्य प्रदेश में 9वें बाघ आरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित होगा।

- समिति ने पार्क में एक नर और एक मादा बाघ को छोड़ने की अनुमति भी प्रदान की।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- प्रस्तावित बाघ अभयारण्य क्षेत्र:
 - ◆ इसका विस्तार 1,751 वर्ग किलोमीटर होगा, जिसमें 300 वर्ग किलोमीटर का मुख्य क्षेत्र शामिल होगा।
 - ◆ 75 वर्ग किलोमीटर और 1,276 वर्ग किलोमीटर का बफर जोन होगा।
 - ◆ सफल प्रजनन कार्यक्रम के बाद, माधव राष्ट्रीय उद्यान ने सितंबर 2024 में बाघ शावकों के जन्म के साथ बाघ संरक्षण में एक मील का पत्थर स्थापित किया।
- बाघ पुनःप्रवेश का दूसरा चरण:
 - ◆ मध्य प्रदेश वन विभाग पुनः बाघों को लाने के दूसरे चरण की तैयारी कर रहा है, जिसमें बांधवगढ़, कान्हा या संजय-दुबरी राष्ट्रीय उद्यानों से अतिरिक्त बाघों को लाना शामिल है।
- दीर्घकालिक विस्तार योजनाएँ:
 - ◆ माधव टाइगर रिजर्व पाँच वर्षों के भीतर 1,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तार करने की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है।
 - ◆ 100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले बाघ सफारी की भी योजना बनाई गई है, जिसमें 20 करोड़ रुपये का बुनियादी ढाँचा निवेश होगा, जिससे पारिस्थितिकी पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की आशा है।
- संरक्षण और पारिस्थितिक पर्यटन लाभ:
 - ◆ इस पहल का उद्देश्य माधव और कुनो राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यजीव प्रबंधन को सुदृढ़ करना है।
 - ◆ इस परियोजना से इको-पर्यटन को बढ़ावा मिलने तथा स्थानीय समुदायों को लाभ मिलने तथा क्षेत्रीय विकास में योगदान मिलने की आशा है।
- मध्य प्रदेश की लंबित अधिसूचनाएँ:
 - ◆ रातापानी वन्यजीव अभयारण्य, जिसे वर्ष 2008 में बाघ अभयारण्य के रूप में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी, अभी भी आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार कर रहा है।
 - ◆ रिपोर्टों से पता चलता है कि रातापानी के निकट खनन गतिविधियों के कारण राजनीतिक प्रतिरोध के कारण इसके औपचारिक नामकरण में देरी हुई है।

माधव राष्ट्रीय उद्यान

- परिचय:
 - ◆ माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है।
 - ◆ यह ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का एक हिस्सा है।
 - ◆ यह पार्क मुगल बादशाहों और ग्वालियर के महाराजाओं का शिकारगाह था। इसे वर्ष 1959 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला।
- पारिस्थितिकी तंत्र:
 - ◆ इसमें विविध पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें झीलें, शुष्क पर्णपाती और शुष्क कांटेदार वन शामिल हैं।
 - ◆ यह वन बाघों, तेंदुओं, नीलगाय, चिंकारा (गजेला बेनेट्टी) और चौसिंघा (टेट्रासेरस क्वाड्रिकॉर्निस) तथा हिरणों (चीतल, सांभर और बार्किंग डियर) का पर्यावास है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



● बाघ गलियारा:

- ◆ यह पार्क देश के 32 प्रमुख बाघ गलियारों में से एक के अंतर्गत आता है, जो बाघ संरक्षण योजना के माध्यम से संचालित होते हैं। बाघ संरक्षण योजना **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के तहत कार्यान्वित की जाती है।

मध्य प्रदेश में प्रधान डाकघर का आधुनिकीकरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ने मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में प्रधान डाकघर की आधारशिला रखी।

मुख्य बिंदु

● प्रधान डाकघर:

- ◆ प्रधान डाकघर का निर्माण 2.1 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसका निर्माण एक वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- ◆ इस सुविधा में ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिये आधुनिक सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक **प्रौद्योगिकी-सक्षम बुनियादी ढाँचा** उपलब्ध होगा।
- ◆ प्रधान डाकघर अशोकनगर जिले के 10 उप-डाकघरों के लिये प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
 - इसका उद्देश्य सेवा वितरण में सुधार करना और स्थानीय आबादी को अधिक सुविधा प्रदान करना है।

● भारतीय डाक की विरासत:

- ◆ 150 वर्षों से अधिक की सेवा के साथ, भारतीय डाक विश्व स्तर पर सबसे बड़े डाक नेटवर्कों में से एक बना हुआ है।
- ◆ **भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898** को निरस्त करते हुए **डाकघर अधिनियम 2023** लागू हुआ।
- ◆ विभाग आधुनिकीकरण और ज़मीनी स्तर पर पहुँच पर विशेष ध्यान देते हुए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अंतराल को पाटने और उत्कृष्टता प्रदान करने का कार्य जारी रखे हुए है।

भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898

- यह अधिनियम 1 जुलाई, 1898 को भारत में डाकघरों से संबंधित कानून को **समेकित और संशोधित करने** के उद्देश्य से लागू हुआ।
- यह केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली **डाक सेवाओं के विनियमन का प्रावधान करता है।** यह विधेयक केंद्र सरकार को **पत्रों के संप्रेषण पर विशेष विशेषाधिकार प्रदान करता है** तथा पत्रों के संप्रेषण पर केंद्र सरकार का एकाधिकार स्थापित करता है।

विश्व AIDS दिवस 2024 पर इंदौर में कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सभागार में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में **विश्व AIDS दिवस, 2024** स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया।

इस कार्यक्रम में **“सही रास्ता अपनाएँ”** थीम पर जोर दिया गया, जिसमें **HIV/AIDS** से प्रभावित व्यक्तियों के लिये समान अधिकार, सम्मान और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच पर प्रकाश डाला गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- सरकार की प्रतिबद्धता:
 - ◆ केंद्रीय मंत्री ने HIV/AIDS से पीड़ित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिये सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें कानूनी सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच और सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
 - ◆ उन्होंने जागरूकता बढ़ाने, रूढ़िवादिता से निपटने तथा सामुदायिक पहलों और अभियानों के माध्यम से AIDS पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
 - ◆ यह कार्यक्रम 2030 तक AIDS को समाप्त करने के वैश्विक सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के अनुरूप है।
 - ◆ गतिविधियों में सामूहिक कार्रवाई, समानुभूति और अनुकूलता पर जोर दिया गया तथा भेदभाव और भय से मुक्त विश्व को बढ़ावा दिया गया।
- AIDS नियंत्रण में उपलब्धियाँ:
 - ◆ भारत में 2010 से नए HIV मामलों में 44% की कमी देखी गई है , जबकि वैश्विक कमी दर 39% है।
 - इसी अवधि के दौरान देश में AIDS से संबंधित मौतों में 79% की कमी आई।
 - ◆ भारत अब सस्ती, प्रभावी HIV दवाओं के उत्पादन में वैश्विक अग्रणी है और AIDS रोगियों को मुफ्त एंटीरेट्रोवाइरल थैरेपी (ART) प्रदान करता है।
- रणनीतिक लक्ष्य:
 - ◆ भारत ने AIDS के 90% मामलों का पता लगाने, 90% का एआरटी से उपचार करने तथा उपचारित 90% व्यक्तियों में वायरल लोड को कम करने के लिये 90-90-90 का लक्ष्य अपनाया।
 - ◆ संशोधित 95-95-95 लक्ष्य प्राप्ति के निकट हैं, जिसमें 81% की पहचान हो चुकी है, 88% का उपचार हो चुका है तथा 97% में विषाणु दमन का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है।
- मध्य प्रदेश की भूमिका:
 - ◆ मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में राज्य की प्रगति की सराहना की, जिसमें 2028 तक AIDS को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये खतरा मानने की योजना भी शामिल है, जो वैश्विक लक्ष्य 2030 से दो वर्ष पहले है।
 - ◆ उन्होंने मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का उल्लेख किया, जो 5 से बढ़कर 31 हो गई है तथा 2026 तक इनकी संख्या 50 करने की योजना है।
- प्रमुख पहल और विज्ञप्तियाँ:
 - ◆ संकल्प 6वाँ संस्करण: भारत में AIDS नियंत्रण की प्रगति का विवरण।
 - ◆ भारत HIV अनुमान 2023: HIV प्रसार, घटना और मृत्यु दर पर अद्यतन डेटा प्रदान करना।
 - ◆ कॉफी टेबल बुक: गहन सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती हुई।
 - ◆ रोकथाम प्रगति अद्यतन 2023-2024: उच्च जोखिम वाले समूहों के लिये रोकथाम गतिविधियों पर रिपोर्टिंग।
 - ◆ अनुसंधान संकलन खंड II: AIDS पर राज्य-विशिष्ट अध्ययनों से प्राप्त अंतर्दृष्टि को साझा करना।
- सामुदायिक सहभागिता:
 - ◆ इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय AIDS नियंत्रण संगठन (NACO) द्वारा प्रदर्शनियाँ, एक नए लॉन्च किये गए थीम गीत का लाइव प्रदर्शन और राष्ट्रीय AIDS नियंत्रण कार्यक्रम के लाभार्थियों की कहानियाँ शामिल थीं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
कलासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ नीति निर्धारकों, स्वास्थ्य पेशेवरों, नागरिक समाज और विकास सहयोगियों सहित विभिन्न हितधारकों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी की और सहयोग को प्रोत्साहित किया।

HIV/AIDS रोग

परिचय:

- ◆ मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV) एक संक्रमण है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है।
- ◆ एड्स HIV संक्रमण का अंतिम चरण है, जो तब उत्पन्न होता है जब वायरस के प्रभाव से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती है।
- ◆ HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में **CD4 नामक श्वेत रक्त कोशिका (T कोशिका)** पर हमला करता है।
- ◆ T कोशिकाएँ वे कोशिकाएँ हैं जो शरीर में घूमकर कोशिकाओं में विसंगतियों और संक्रमणों का पता लगाती हैं।
- ◆ शरीर में प्रवेश करने के बाद, **HIV खुद को गुणा करता है और सीडी 4 कोशिकाओं को नष्ट कर देता है**, जिससे मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को गंभीर नुकसान पहुँचता है। एक बार यह वायरस शरीर में प्रवेश कर जाए तो इसे कभी भी हटाया नहीं जा सकता।
- ◆ HIV से संक्रमित व्यक्ति का CD4 काउंट काफी कम हो जाता है। स्वस्थ शरीर में CD4 काउंट 500-1600 के बीच होता है, लेकिन संक्रमित शरीर में यह 200 तक भी कम हो सकता है।

संचरण:

- ◆ HIV विभिन्न स्रोतों के माध्यम से फैल सकता है, जब किसी HIV संक्रमित व्यक्ति के शरीर के कुछ तरल पदार्थों के साथ सीधा संपर्क होता है, जिसमें वायरल लोड का पता लगाया जा सकता है। यह संपर्क रक्त, वीर्य, मलाशय द्रव, योनि द्रव या स्तन के दूध के माध्यम से हो सकता है।

लक्षण:

- ◆ एक बार जब HIV AIDS में परिवर्तित हो जाता है तो इसके प्रारंभिक लक्षण अस्पष्टीकृत थकान, बुखार, जननांगों या गर्दन के आसपास घाव, निमोनिया आदि हो सकते हैं।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने **स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G)** को दृढ़ करने के लिये पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार के ग्रामीण स्वच्छता के लिये जिम्मेदार राज्य मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।

- इस सत्र का उद्देश्य प्रगति का आकलन करना, चुनौतियों से निपटना तथा ग्रामीण भारत में स्थायी स्वच्छता परिणाम सुनिश्चित करने के लिये रणनीतियों को कारगर बनाना था।

मुख्य बिंदु

- केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता को एक व्यावहारिक मिशन बताया जो ग्रामीण समुदायों के स्वास्थ्य और सम्मान के लिये महत्वपूर्ण है।
- उन्होंने सामूहिक प्रयासों के माध्यम से स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के निर्माण के महत्त्व को रेखांकित किया तथा कहा कि प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की अपनी अलग-अलग चुनौतियाँ हैं, लेकिन स्वच्छ भारत प्राप्त करने का लक्ष्य उनका समान है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- राज्यवार प्रगति:
- मध्य प्रदेश:
 - ◆ 99% गाँव खुले में शौच मुक्त (ODF) प्लस स्थिति वाले हैं, जिनमें से 95% ने ODF प्लस मॉडल का दर्जा प्राप्त कर लिया है।
 - ◆ राज्य ने RRDA भोपाल के साथ समझौता ज्ञापन सहित नवीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल को क्रियान्वित किया।
- उत्तर प्रदेश:
 - ◆ 98% गाँव ODF प्लस हैं। SBM-G उद्देश्यों के लिये 1 लाख से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है।
 - ◆ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिये अपशिष्ट से ऊर्जा मॉडल और स्क्रेप डीलर संपर्क पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- बिहार:
 - ◆ 92% गाँव ODF प्लस हैं। ग्रे वाटर मैनेजमेंट कवरेज 91% है और टोस अपशिष्ट प्रबंधन 80% है।
 - ◆ प्रयास कम प्रदर्शन करने वाले जिलों में परिणामों को बेहतर बनाने पर केंद्रित हैं।
- पंजाब:
 - ◆ 98% गाँव ODF प्लस हैं, जिनमें से 87% ने ग्रे वाटर प्रबंधन संतुष्टि प्राप्त कर ली है।
 - ◆ उन्नत प्रणालियाँ विकसित की जा रही हैं।
- सामूहिक कार्रवाई के लिये मंत्री का मार्गदर्शन:
 - ◆ ODF प्लस स्थिरता: ODF प्लस मॉडल गाँवों को सत्यापित करने और बनाए रखने के लिये मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना।
 - ◆ अपशिष्ट प्रबंधन अंतराल : घरेलू स्तर के समाधानों को प्राथमिकता देकर टोस और धूसर जल प्रबंधन में अंतराल को दूर करना।
 - ◆ सामुदायिक स्वच्छता: सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की कार्यक्षमता और परिसंपत्ति प्रबंधन को मजबूत करना।
 - ◆ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ साझेदारी बनाना और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) ढाँचे का उपयोग करना।
 - EPR उत्पादकों को उनके उत्पादों के जीवन चक्र के दौरान उनके पर्यावरणीय प्रभावों के लिये जिम्मेदार बनाता है। इसका उद्देश्य बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना और नगर पालिकाओं पर बोझ कम करना है।
 - ◆ व्यवहार में परिवर्तन: लक्षित IEC (सूचना शिक्षा और संचार) अभियानों के माध्यम से शौचालय के निरंतर उपयोग और अपशिष्ट पृथक्करण को बढ़ावा देना।
 - ◆ समुदाय-नेतृत्व वाले दृष्टिकोण: राज्यों को समुदाय-नेतृत्व वाले स्वच्छता प्रयासों को बढ़ावा देने के लिये महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय नेताओं और निजी क्षेत्र के उद्यमों को शामिल करना होगा।
- व्यापक दृष्टिकोण और वैश्विक संरक्षण:
 - ◆ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण परिवर्तन की आधारशिला है, जो स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और सामुदायिक कल्याण को एकीकृत करता है।
 - ◆ यह मिशन वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसमें SDG 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) और SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) शामिल हैं।
 - ◆ इसका ध्यान लक्ष्य से आगे बढ़कर स्वास्थ्य, सम्मान और आत्मनिर्भरता के पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
कलासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G)

● परिचय:

- ◆ इसे वर्ष 2014 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिये लॉन्च किया गया था।
- ◆ इस मिशन को एक राष्ट्रव्यापी अभियान/जनआंदोलन के रूप में क्रियान्वित किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करना था।

● स्वच्छ भारत मिशन (G) चरण-I:

- ◆ 2 अक्टूबर, 2014 को SBM (G) के शुभारंभ के समय देश में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 38.7% बताया गया था।
- ◆ मिशन के शुभारंभ के बाद से 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप, सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने 2 अक्टूबर, 2019 तक खुद को ODF घोषित कर दिया है।

● SBM (G) चरण-II:

- ◆ यह चरण-I के अंतर्गत उपलब्धियों की स्थिरता पर जोर देता है तथा ग्रामीण भारत में ठोस/तरल एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) के लिये पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करता है।
- ◆ इसे वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा, जिसका कुल परिव्यय 1,40,881 करोड़ रुपए होगा।
- ◆ ODF प्लस के SLWM घटक की निगरानी 4 प्रमुख क्षेत्रों के आउटपुट-आउटकम संकेतकों के आधार पर की जाएगी:
- ◆ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन
- ◆ जैवनिम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (पशु अपशिष्ट प्रबंधन सहित)
- ◆ ग्रेवाटर (घरेलू अपशिष्ट जल) प्रबंधन
- ◆ मल-कीचड़ प्रबंधन।

मध्य प्रदेश में नई योजनाएँ शुरू

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में 'जन कल्याण पर्व' और 'मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान' की शुरुआत की। इन दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य उनके कार्यकाल के दौरान किये गए कार्यों को उजागर करना और अधिक से अधिक लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है।

मुख्य बिंदु

● जन कल्याण पहल:

- ◆ जन कल्याण पर्व 11 से 26 दिसंबर 2024 तक मनाया जाएगा, जिसमें विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा।
- ◆ मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान 11 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी, 2025 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य घर-घर जाकर सर्वेक्षण के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ ये पहल गीता जयंती के अवसर पर की गई है, जो भगवान कृष्ण द्वारा श्रीमद्भागवत गीता के वाचन की याद में मनाई जाती है।
- अभियान का फोकस:
 - ◆ ये अभियान गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को लक्ष्य बनाकर उन्हें निम्नलिखित से जोड़ते हैं:
 - 34 लाभार्थी-उन्मुखी योजनाएँ
 - 11 लक्ष्य-आधारित योजनाएँ
 - 63 सेवाएँ
 - ◆ इसका उद्देश्य नये अवसर प्रदान करना तथा कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करना है।
- सांस्कृतिक मान्यता और उपलब्धियाँ:
 - ◆ गीता महोत्सव में 3,721 आचार्यों और बटुकों सहित 7,000 से अधिक लोगों ने गीता श्लोकों के सामूहिक पाठ में भाग लिया।
 - ◆ इस उपलब्धि को गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मान्यता मिली और मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को बधाई दी।

बैगा आदिवासी कलाकार जोधड़या बाई का निधन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रसिद्ध बैगा आदिवासी कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जोधड़या बाई का लंबी बीमारी के बाद मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में निधन हो गया।

मुख्य बिंदु

- बैगा जनजातीय कला में योगदान:
- जोधड़या बाई ने बैगा जनजातीय कला को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिये उन्हें वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- मुख्यमंत्री की ओर से संवेदना:
- मुख्यमंत्री ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश और देश ने एक ऐसी कलाकार खो दी है, जिसने अपना जीवन आदिवासी संस्कृति, कला और परंपराओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिये समर्पित कर दिया।

बैगा जनजाति

- बैगा (जिसका अर्थ है जादूगर) विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) में से एक है।
- वे मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रहते हैं।
- परंपरागत रूप से बैगा अर्द्ध-खानाबदोश जीवन व्यती करते थे और कटाई-जलाकर खेती करते थे। अब वे अपनी आजीविका के लिये मुख्य रूप से लघु वनोपज पर निर्भर हैं।
- बाँस प्राथमिक संसाधन है।
- टैटू बनवाना बैगा संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, प्रत्येक आयु और शरीर के हिस्से के लिये एक विशेष टैटू निर्धारित होता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
कलासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मध्य प्रदेश ने चीता के लिये नया आवास बनाने की योजना

चर्चा में क्यों ?

गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के लिये चीता कार्य योजना में चीता आनुवंशिकी का विश्लेषण, तेंदुओं को स्थानांतरित करना और वर्ष 2025 में चीता के पुनः परिचय की तैयारी के लिये शिकार की संख्या को बढ़ाना शामिल है।

मुख्य बिंदु

- चीता परिचय हेतु कार्य योजना:
 - ◆ प्रारंभिक रिलीज: अभयारण्य के पश्चिमी रेंज में 64 वर्ग किलोमीटर के शिकारी-रोधी बाड़े में 6-8 चीतों को लाया जाएगा।
 - ◆ शिकार आधार: इस क्षेत्र में चिंकारा, नीलगाय और अन्य प्रजातियों सहित पर्याप्त शिकार उपलब्ध है, अनुमानतः प्रतिवर्ष 1,560-2,080 शिकार पशुओं की आवश्यकता होती है।
 - ◆ वर्तमान में शिकार की उपलब्धता: इस क्षेत्र में वर्तमान में 475 जानवर हैं तथा चीतल और काले हिरण जैसे 1,500 अतिरिक्त शिकार भी हैं।

तेंदुए की चुनौती और शमन:

- ◆ तेंदुए की जनसंख्या: पश्चिमी रेंज में लगभग 70 तेंदुए हैं, जो शिकार के लिये प्रतिस्पर्धा के कारण चीतों, विशेषकर उनके शावकों के लिये खतरा उत्पन्न करते हैं।
- ◆ तेंदुओं का स्थानांतरण: चीतों को वहाँ लाए जाने से पहले बाड़ वाले क्षेत्र के सभी तेंदुओं को पकड़ लिया जाएगा और उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- ◆ वर्तमान रणनीति: यह प्रयास चीता जनसंख्या को स्थिर करने के लिये एक दशक से अधिक समय से चल रही रणनीति का हिस्सा है, जिसमें मांसाहारी अंतःक्रियाओं पर अनुसंधान के लिये 10 तेंदुओं की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) ट्रैकिंग भी शामिल है।
- चीता जनसंख्या और आनुवंशिक रणनीति:
 - ◆ चीतों का आयात: आनुवंशिक रूप से विविध आबादी बनाने के लिये अफ्रीकी रिजर्वों से 12-14 चीतों (8-10 नर, 4-6 मादा) की आबादी का आयात किया जाएगा।
 - ◆ आनुवंशिक विविधता: अंतःप्रजनन से बचने के लिये चीतों का चयन आनुवंशिक अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा, जिसका विश्लेषण माइक्रो-सैटेलाइट और जीनोमिक तकनीकों का उपयोग करके किया जाएगा।
 - ◆ व्यक्तिगत निगरानी: जनसांख्यिकीय अध्ययन और उत्तरजीविता एवं स्वास्थ्य की निगरानी के लिये चीता प्रोफाइल बनाए रखा जाएगा।
- पारिस्थितिक प्रभाव और शिकार प्रजाति प्रबंधन:
 - ◆ पारिस्थितिकीय प्रभाव: चीतों के आने से शिकार प्रजातियों के व्यवहार पर असर पड़ेगा, जिसके लिये काले हिरण, चीतल और नीलगाय की आवश्यकता होगी।
 - ◆ शिकार को रेडियो कॉलर लगाना: कुछ शिकार जानवरों को रेडियो कॉलर लगाया जाएगा ताकि नए शिकारियों की उपस्थिति के प्रति उनके अनुकूलन का अध्ययन किया जा सके।
 - ◆ जीर्णोद्धार योजनाएँ: अभयारण्य के आवास का जीर्णोद्धार एक व्यापक चीता संरक्षण योजना का हिस्सा है, जिसमें राजस्थान के भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जैसे अन्य स्थलों को भी चीता आबादी के लिये चिह्नित किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- चीता की वर्तमान स्थिति:

- ◆ कुनो राष्ट्रीय उद्यान में वर्तमान में 24 चीते (12 शावकों सहित) हैं, जिनमें से दो चीतों को हाल ही में खुले वन में छोड़ा गया है।

गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य

- स्थान:

- ◆ 1974 में अधिसूचित, इसमें राजस्थान की सीमा से लगे पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले शामिल हैं।
- ◆ चंबल नदी इस अभयारण्य को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है तथा गांधी सागर बाँध भी अभयारण्य के भीतर स्थित है।

- पारिस्थितिकी तंत्र:

- ◆ इसके पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता इसकी चट्टानी भूमि और उथली ऊपरी मृदा है, जो सवाना पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन प्रदान करती है।
- ◆ इसमें सूखे पर्णपाती वृक्षों और झाड़ियों से भरे खुले घास के मैदान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अभयारण्य के भीतर नदी घाटियाँ सदाबहार हैं।

भारत का पहला ज़ीरो-वेस्ट हवाई अड्डा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा 3000 वर्ग फुट सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा के उद्घाटन के साथ भारत का पहला ज़ीरो-वेस्ट हवाई अड्डा बन गया।

- अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली:

- ◆ नई सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा में हवाई अड्डे और विमान दोनों से अपशिष्ट को अलग करने और पुनर्चक्रित करने के लिये एक व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की सुविधा है।
- ◆ गीले अपशिष्ट को उर्वरक में परिवर्तित किया जाएगा, जो 4R सिद्धांत पर आधारित हवाई अड्डे की ज़ीरो-वेस्ट पहल के अनुरूप होगा: **Reduce, Reuse, Recycle, and Recover** (कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रित करना, पुनर्स्थापित करना)।

- विस्तृत योजनाएँ:

- ◆ इसके अलावा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में इंदौर हवाई अड्डे की क्षमता 40 लाख यात्रियों से बढ़ाकर 90 लाख यात्री प्रति वर्ष कर दी जाएगी।
- ◆ थाईलैंड और अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये एयरलाइनों के साथ चर्चा चल रही है।

- बुनियादी ढाँचा विकास:

- ◆ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने हवाई अड्डे पर 55 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए हवाई यातायात नियंत्रण टावर का भी उद्घाटन किया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



MP हाईकोर्ट ने मंदसौर में बूचड़खाने को NOC दी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंदसौर में एक नगर निगम अधिकारी को भैंस वधशाला के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) देने का आदेश दिया है तथा अनुमति देने से इनकार करने को "अस्वीकार्य" बताया है।

मुख्य बिंदु

- स्थानीय निकाय का तर्क:
- स्थानीय निकाय ने यह कहते हुए NOC आवेदन अस्वीकार कर दिया कि मंदसौर एक धार्मिक नगर है, इसलिये यहाँ बूचड़खाने की अनुमति देना अनुचित है।
- न्यायालय ने सुनवाई के दौरान इस तर्क को "पूरी तरह अस्वीकार्य" करार दिया।
- पवित्र क्षेत्र:
- राज्य सरकार ने 9 दिसंबर 2011 की अधिसूचना में मंदसौर में भगवान शिव के पशुपतिनाथ मंदिर के चारों ओर 100 मीटर के दायरे को "पवित्र क्षेत्र (Sacred Area)" घोषित किया।
- न्यायालय का अवलोकन:
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना के आधार पर पूरे शहर को पवित्र क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

पशुपतिनाथ मंदिर

- इसे मंदसौर शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
- यह शिवना नदी पर स्थित है और अपने आठ मुख वाले शिवलिंग के लिये जाना जाता है। मंदिर की मूर्तियाँ 5वीं या 6वीं शताब्दी की हैं।
- यह चिकने, गहरे ताँबे जैसे चट्टान के ब्लॉक से बना है।
- मंदिर में 100 किलो सोने से मढ़ा (सजाया) गया एक घड़ा भी स्थित है।

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान

चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश वन विभाग के अनुसार, भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को गुजरात से दो एशियाई शेर प्राप्त होंगे, जबकि इसके बदले में दो बंगाल टाइगर भेजे जाएँगे।

मुख्य बिंदु

- मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच आदान-प्रदान:
 - ◆ पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत दो बाघों को जूनागढ़ चिड़ियाघर में स्थानांतरित किया गया है।
 - ◆ इस आदान-प्रदान के तहत दो शुद्ध नस्ल के एशियाई (गिर) शेरों को जूनागढ़ के सक्करबाग प्राणी उद्यान से भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप





एशियाई शेर (Panthera leo persica)



आवास:

- ❖ वर्तमान में गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य (गुजरात) एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है।

संरक्षण स्थिति:

- ❖ IUCN रेड लिस्ट: संकटापन्न (Endangered)
- ❖ CITES: परिशिष्ट I
- ❖ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची I

खतरे:

- ❖ मानव-वन्यजीव संघर्ष
- ❖ अवैध शिकार
- ❖ आनुवंशिक अंतःप्रजनन (जेनेटिक इनब्रीडिंग)
- ❖ प्लेग, कैनाइन डिस्टेपर जैसे रोग

संरक्षण हेतु प्रयास:

- ❖ एशियाई शेर संरक्षण परियोजना
- ❖ प्रोजेक्ट लायन
- ❖ विश्व शेर दिवस (10 अगस्त)

विशेषताएँ:

- ❖ एशियाई शेर अफ्रीकी शेर से थोड़े छोटे होते हैं।
- ❖ सबसे अनूठी शारीरिक विशेषता जो कि एशियाई शेर में अक्सर देखी जाती है वह है इनके पेट के साथ त्वचा की एक अनुदैर्घ्य परत जो कि अफ्रीकी शेर में शायद ही पाई जाती है।

● वन विहार राष्ट्रीय उद्यान:

- ◆ यह भोपाल में बड़ी झील के तट पर स्थित है और मध्य प्रदेश की राजधानी में एक महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।
- ◆ इसे राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर, वन्य प्राणियों के लिये बचाव केंद्र तथा चयनित महत्वपूर्ण प्रजातियों के लिये संरक्षण प्रजनन केंद्र का संयोजन होने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है।
 - यह मध्य भारत का एकमात्र स्थान है, जहाँ इसके बचाव केंद्र में सर्कसों से बचाए गए शेरों और बाघों, मदारियों से बचाए गए भालुओं, मानव-वन्यजीव संघर्ष वाले क्षेत्रों से बचाए गए बाघों, पैंथरों और भालुओं को रखा गया है।
 - यह मध्य प्रदेश के राज्य पशु हार्ड ग्राउंड बारासिंघा और जिप्सी गिद्ध की दो प्रजातियों के लिये एक नामित समन्वय चिड़ियाघर और संरक्षण प्रजनन केंद्र भी है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ यह विभिन्न प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों का प्राकृतिक आवास है, जैसे **बाघ**, **सफेद बाघ**, **तेंदुआ**, **लकड़बग्घा**, **भालू**, **चीतल**, **सांभर**, **काला हिरण**, **नीलगाय**, **चौसिंगा**, **लंगूर**, **रीसस बंदर**, **साही** आदि।

प्रधानमंत्री ने केन-बेतवा परियोजना की आधारशिला रखी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में **केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना** की आधारशिला रखी।

- यह **राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति** के तहत **पहली ऐसी पहल** है।

मुख्य बिंदु

- **केन-बेतवा लिंक परियोजना:**
 - ◆ इस परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश के 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना है।
 - ◆ 2,000 गाँवों के 7.18 लाख किसान परिवारों को उन्नत **सिंचाई सुविधा** का लाभ मिलेगा।
 - ◆ इस परियोजना से 103 मेगावाट **जल विद्युत** और 27 मेगावाट **सौर ऊर्जा** उत्पन्न होगी।
 - ◆ यह परियोजना केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सहयोग का प्रतीक है, जो दिवंगत प्रधानमंत्री **अटल बिहारी वाजपेयी** के नदी-जोड़ो के सपने को साकार करती है।
- **आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव:**
 - ◆ सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिये पर्याप्त जल सुनिश्चित करना।
 - ◆ **बुंदेलखंड** में आर्थिक विकास, **पर्यटन** और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना।
 - ◆ **सूखा प्रभावित बुंदेलखंड** क्षेत्र में भूजल की कमी को दूर करना।
- **संरक्षण प्रयास:**
 - ◆ छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में चंदेल-युग के विरासत तालाबों को पुनर्स्थापित करने पर ध्यान देना।
 - ◆ **पन्ना टाइगर रिजर्व** में वन्य प्राणियों को निरंतर जल आपूर्ति।
 - ◆ उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले के लिये बाढ़ राहत।

राष्ट्रीय नदी जोड़ प्राधिकरण

- राष्ट्रीय स्तर पर नदियों को जोड़ने (ILR) का विचार यह है कि नदियों को आपस में जोड़ा जाना चाहिये, ताकि **जल की कमी** की समस्या को दूर करने के लिये अधिशेष नदियों और क्षेत्रों से जल को कमी वाले क्षेत्रों और नदियों में स्थानांतरित किया जा सके।
- इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1982 में **राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA)** की स्थापना हुई।

मध्य प्रदेश में बाघों को स्थानांतरित किया जाएगा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** ने मध्य प्रदेश से 15 **बाघों** को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों में स्थानांतरित करने की मंजूरी प्रदान की है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- बाघों का सबसे बड़ा स्थानांतरण:
 - ◆ यह पहल भारत में किसी एक राज्य से बड़ी बिल्लियों (बिग कैट्स) के सबसे बड़े स्थानांतरण का प्रतीक होगी।
 - इसका उद्देश्य देश भर में बाघ संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना है।
 - ◆ स्थानांतरण के लिये कोई विशिष्ट समयसीमा अभी तक तय नहीं की गई है।
 - ◆ तीन रिजर्वों से बाघों को स्थानांतरित किया जाएगा: बाँधवगढ़, पेंच और कान्हा टाइगर रिजर्व।
 - ◆ कुल स्थानांतरित बाघों में से बारह बाघिन होंगी।
 - ◆ गंतव्य राज्य और वितरण:
 - ◆ राजस्थान: चार बाघिन।
 - ◆ छत्तीसगढ़: दो बाघ और छह बाघिन।
 - ◆ ओडिशा: एक नर बाघ और दो बाघिन।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

- यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है।
- इसकी स्थापना वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी।
- इसका गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (जैसा कि वर्ष 2006 में संशोधित किया गया) के प्रावधानों के तहत किया गया था, ताकि इसे निर्दिष्ट की गई शक्तियों और कार्यों के अनुसार बाघ संरक्षण को सशक्त किया जा सके

बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व

- यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है और विन्ध्य पहाड़ियों पर विस्तृत है।
- यह ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसका प्रमाण प्रसिद्ध बाँधवगढ़ किले के साथ-साथ संरक्षित क्षेत्र में मौजूद अनेक गुफाएँ, शैलचित्र और नक्काशी हैं।
- 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तथा 1993 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया।
- यह रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिये जाना जाता है।
- अन्य महत्वपूर्ण शिकार प्रजातियों में चीतल, सांभर, भौंकने वाला हिरण, नीलगाय, चिंकारा, जंगली सुअर, चौंसिंघा, लंगूर और रीसस मकाँक शामिल हैं।
- बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया और सियार जैसे प्रमुख शिकारी इन पर निर्भर हैं।

पेंच टाइगर रिजर्व (PTR)

- PTR मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों का संयुक्त गौरव है।
- यह अभयारण्य मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है तथा महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक अलग अभयारण्य के रूप में विस्तृत है।
- इसे 1975 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तथा वर्ष 1992 में इसे बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया।
- हालाँकि, 1992-1993 में PTR मध्य प्रदेश को भी यही दर्जा दिया गया था। यह सेंट्रल हाइलैंड्स के सतपुड़ा-मैकल पर्वतमाला के प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में से एक है।
- यह भारत के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों (IBA) के रूप में अधिसूचित स्थलों में से एक है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- कान्हा टाइगर रिज़र्व
- यह मध्य प्रदेश के दो जिलों- मंडला और बालाघाट- में 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है।
- वर्तमान कान्हा क्षेत्र को दो अभयारण्यों, हालोन और बंजार में विभाजित किया गया था। 1955 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 1973 में इसे कान्हा टाइगर रिज़र्व बना दिया गया।

मध्य प्रदेश विषाक्त अपशिष्ट का निपटान करेगा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष पश्चात, भोपाल में यूनिचन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) से निकले 337 टन जहरीले अपशिष्ट का निपटान शुरू कर दिया है। वे इस अपशिष्ट को धार जिले के पीथमपुर ले जाने की योजना बना रहे हैं।

मुख्य बिंदु

- पर्यवेक्षित पैकिंग और स्टैकिंग:
 - ◆ फैक्ट्री प्रशासन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) की देख-रेख में अपशिष्ट की पैकिंग और स्टैकिंग का काम कर रहा है।
 - ◆ पैकिंग और लोडिंग प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी शामिल होते हैं तथा आवश्यक सावधानियाँ बरतते हैं।
 - ◆ अपशिष्ट के लिये बारह विशेष रूप से डिज़ाइन किये गए वायुरोधी कंटेनरों का उपयोग किया जा रहा है।
- लघु श्रमिक शिफ्ट:
 - ◆ विषाक्त अपशिष्ट के संपर्क को न्यूनतम करने के लिये श्रमिक नियमित 8-9 घंटे की शिफ्ट के स्थान पर 30-45 मिनट की शिफ्ट में काम कर रहे हैं।
 - ◆ भोपाल से पीथमपुर तक अपशिष्ट के सुरक्षित परिवहन के लिये 250 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है।
- परीक्षण और सुरक्षा आश्वासन:
 - ◆ वर्ष 2015 में, वैज्ञानिक देखरेख में पीथमपुर में 10 टन अपशिष्ट को जला दिया गया था, जिसके परिणाम उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किये गये थे, जिसमें कोई हानिकारक प्रभाव नहीं दिखाया गया था।
 - ◆ सुरक्षा उपायों में संदूषण को रोकने के लिये लैंडफिल स्थलों पर दो-परत वाली झिल्ली और चार-परत वाली वायु निस्पंदन प्रणाली लगाना शामिल है।

भोपाल गैस त्रासदी

- भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी, जब मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, जिसमें 5,479 लोग मारे गए थे।
- पाँच लाख से अधिक लोगों को दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव झेलना पड़ा तथा इस त्रासदी से संबंधित अनेक मामले अभी भी न्यायालयों में लंबित हैं।

रक्षा मंत्री ने महु स्थित आर्मी वॉर कॉलेज का दौरा किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के महु स्थित आर्मी वॉर कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने युद्ध के 'अपरंपरागत तरीकों' को देश के सामने नई चुनौतियों के रूप में बताया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- **आधुनिक युद्ध में चुनौतियाँ:**
 - ◆ युद्ध के नए रूप जैसे सूचना युद्ध, AI-आधारित युद्ध, छद्म युद्ध, विद्युत-चुंबकीय युद्ध, अंतरिक्ष युद्ध और साइबर हमले प्रमुख चुनौतियों के रूप में उभर रहे हैं।
 - ◆ इलेक्ट्रॉनिक चिप उत्पादन में प्रभुत्व और दुर्लभ मृदा सामग्रियों पर एकाधिकार भी इन चुनौतियों में योगदान दे रहे हैं।
 - ◆ हाइब्रिड युद्ध और ग्रेजोन युद्ध सुरक्षा चिंताओं को और अधिक जटिल बनाते हैं।
- **महू प्रशिक्षण केंद्र की भूमिका:**
 - ◆ इस जटिल वातावरण में, भारतीय सेना के लिये सभी संभावित खतरों से निपटने के लिये अच्छी तरह प्रशिक्षित और सुसज्जित रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
 - ◆ महू स्थित प्रशिक्षण केंद्र इन आधुनिक चुनौतियों के लिये सैन्य बलों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 - ◆ महू 200 से अधिक वर्षों से अपनी सैन्य उत्कृष्टता के लिये जाना जाता है, जिसके कारण इसके प्रशिक्षण केंद्र सेना की तैयारी के लिये महत्वपूर्ण हैं।
- **सेनाओं के बीच एकीकरण और संयुक्तता:**
 - ◆ सरकार तीनों सैन्य शाखाओं के बीच एकीकरण और संयुक्तता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
 - ◆ इस दृष्टिकोण का उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिये बलों को बेहतर ढंग से सुसज्जित करना है।
 - ◆ महू छावनी सेना की सभी शाखाओं के अधिकारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करती है।
- **भारत के विकास का विजन:**
 - ◆ भारत का लक्ष्य वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है तथा वर्तमान अवधि को वह परिवर्तन का समय मानता है।
 - ◆ भारतीय सेना निरंतर आधुनिक हथियारों से उन्नत हो रही है, न केवल अपनी सेना को सुसज्जित कर रही है, बल्कि घरेलू स्तर पर निर्मित उपकरणों का निर्यात भी अन्य देशों को कर रही है।
- **रक्षा मंत्री का दौरा:**
 - ◆ रक्षा मंत्री ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर को समर्पित भीम जन्मभूमि स्मारक का दौरा किया, जहाँ उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित की।
 - ◆ उन्होंने डॉ. अंबेडकर की प्रशंसा करते हुए उन्हें निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बताया, जो सामाजिक समानता और सशक्तिकरण के लिये समर्पित थे।

ग्रे-जोन युद्ध

- यह संघर्ष के एक ऐसे स्वरूप को संदर्भित करता है, जिसमें ऐसी कार्रवाइयाँ की जाती हैं जो पारंपरिक युद्ध की सीमा से नीचे होती हैं, लेकिन इनका उद्देश्य अस्पष्टता, अस्वीकार्यता और बल प्रयोग के माध्यम से रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है।
- ग्रे-जोन युद्ध में, विरोधी सीधे खुले युद्ध में शामिल हुए बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये साइबर हमले, आर्थिक दबाव और छद्म संघर्ष जैसी रणनीति अपनाते हैं।
- यह शांति और संघर्ष के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिये गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप

